

## भारत में ऑनलाइन व्यापार के लिए कानूनी नीति और सुरक्षा उपाय

आशीष कुमार पचौरी

वाणिज्य संकाय

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

### प्रस्तावना

भारत में ऑनलाइन व्यापार (ई-कॉमर्स) पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियाँ, उपभोक्ता व्यवहार और बाजार संरचनाएँ बदल रही हैं। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें शुरू की हैं, जिससे ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिला है। हालांकि, इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि इन व्यापारिक गतिविधियों में सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की रक्षा की जाए। ऑनलाइन व्यापार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, धोखाधड़ी से बचाव और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए कानूनी नीति और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। इस शोध पत्र में, हम भारत में ऑनलाइन व्यापार के लिए मौजूदा कानूनी नीति, सुरक्षा उपायों और उन पर होने वाले सुधारों पर चर्चा करेंगे।

### कुजीभूत शब्द –

ऑनलाइन, भारत, व्यापार, ई-कॉमर्स, डिजिटल, कानून और नीतियाँ, साइबर अपराध।

### भारत में ऑनलाइन व्यापार के कानूनी ढांचे

भारत में ऑनलाइन व्यापार के लिए कई कानून और नीतियाँ अस्तित्व में हैं, जो इस क्षेत्र के संचालन को नियंत्रित करती हैं। प्रमुख कानून और नीतियाँ निम्नलिखित हैं:

#### 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

यह अधिनियम भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और लेन-देन की कानूनी वैधता को सुनिश्चित करता है। इस कानून के तहत, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी स्वीकृति दी गई है। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण भाग है धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डेटा चोरी के खिलाफ सुरक्षा उपायों का निर्धारण। यह अधिनियम साइबर अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी प्रदान करता है, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी।

**उदाहरण:** आईटी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी और इंटरनेट पर धोखाधड़ी करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है।

### **2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019**

इस अधिनियम के तहत ऑनलाइन उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। इसमें विशेष रूप से ऑनलाइन व्यापारियों को पारदर्शिता और उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसमें उन पर उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने और सामान की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डाली गई है।

**उदाहरण:** उपभोक्ता यदि ऑनलाइन उत्पाद से संतुष्ट नहीं होते, तो वे 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

### **3. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा कानून**

ऑनलाइन व्यापार में उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है। भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 के तहत डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कड़े नियम प्रस्तावित किए गए हैं। यह बिल उपभोक्ताओं के डेटा को इकट्ठा करने, संग्रहण और प्रसंस्करण के तरीके को नियंत्रित करता है।

**उदाहरण:** इस कानून के तहत, कंपनियाँ उपभोक्ताओं की सहमति के बिना उनका व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा नहीं कर सकतीं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अपने डेटा पर नियंत्रण और संशोधन का अधिकार भी दिया गया है।

### **4. बौद्धिक संपदा अधिकार**

ऑनलाइन व्यापार में उत्पादों, ब्रांडों और सेवाओं की बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में कॉपीराइट कानून, ट्रेडमार्क कानून और पेटेंट कानून लागू होते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामग्री और उत्पादों की बौद्धिक संपदा की रक्षा करते हैं।

**उदाहरण:** जब कोई कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को बेचना चाहती है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि उत्पादों या ब्रांड का बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित हो।

### **ऑनलाइन व्यापार में सुरक्षा उपाय**

- 1. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता:** ऑनलाइन व्यापार में डेटा सुरक्षा के लिए कई तकनीकी उपायों का पालन किया जाता है। एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, और सुरक्षित भुगतान गेटवे जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं का व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा सुरक्षित रहे। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जैसे Amazon और Flipkart अपने भुगतान गेटवे में SSL (Secure Sockets Layer) एन्क्रिप्शन का उपयोग करती हैं ताकि भुगतान के दौरान ग्राहकों के कार्ड विवरण सुरक्षित रहें।
- 2. ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव:** कंपनियाँ अक्सर फर्जी वेबसाइट्स और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए उपाय करती हैं। इसके लिए कंपनियाँ फिशिंग और स्मिशिंग हमलों से बचाव के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों का पालन करती हैं। भारत में बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएँ अपने उपभोक्ताओं को नियमित रूप से धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान करती हैं और उन्हें सुरक्षित लेन-देन के लिए निर्देशित करती हैं।
- 3. मंचों पर कड़ी निगरानी:** ई-कॉमर्स कंपनियाँ अपनी वेबसाइटों और प्लेटफार्मों पर कड़ी निगरानी रखती हैं ताकि उन पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी या गैरकानूनी गतिविधियाँ न हो सकें। इसके लिए वे एंटी-फ्रॉड सॉफ्टवेयर और AI आधारित निगरानी का उपयोग करती हैं।
- 4. ग्राहक सहायता और शिकायत निवारण प्रणाली:** ग्राहकों को उनके मुद्दों का समाधान समय पर प्राप्त हो, इसके लिए कंपनियाँ प्रभावी शिकायत निवारण प्रणालियाँ और हेल्पडेस्क प्रदान करती हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक सरल और स्पष्ट रिटर्न और रिफंड नीति होती है, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके।

### चुनौतियाँ और समाधान

#### 1. धोखाधड़ी और नकली उत्पादों की समस्या

ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर नकली उत्पादों और धोखाधड़ी की समस्या अक्सर सामने आती है। इसके समाधान के लिए सरकार और कंपनियों को मिलकर कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है।  
**समाधान:** सरकार को ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रमाणीकरण और गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

#### 2. नियमों की स्पष्टता का अभाव

कई बार उपभोक्ताओं और कंपनियों को कानूनी नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में अस्पष्टता होती है।

**समाधान:** कानूनी ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना होगा ताकि उपभोक्ताओं और व्यापारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल सकें।

### 3. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियमों का पालन

भारत में ऑनलाइन व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ भी भागीदारी करती हैं, और इससे संबंधित कानूनों की कमी के कारण कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

**समाधान:** भारत को अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के अनुरूप अपने कानूनी ढांचे को सुधारने की आवश्यकता है।

### निष्कर्ष

भारत में ऑनलाइन व्यापार का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, और इसके साथ कानूनी सुरक्षा उपायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, धोखाधड़ी से बचाव और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए कानूनी नीतियाँ और सुरक्षा उपायों का मजबूत होना आवश्यक है। भारत में विभिन्न कानूनी ढाँचों और नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने से ऑनलाइन व्यापार को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकता है।

### संदर्भ सूची

1. Information Technology Act, 2000, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.
2. Consumer Protection Act, 2019, Ministry of Consumer Affairs, Government of India.
3. Personal Data Protection Bill, 2019, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.
4. E-commerce and Consumer Protection, Journal of Consumer Affairs, 2021.
5. Cybersecurity and Data Privacy in India, NASSCOM Report, 2022.